भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1418
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा

1418. **डॉ. आनन्द कुमार गोंड:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन और इसके शैक्षणिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन या समीक्षा की है;
(ख) यदि हाँ, तो उक्त अध्ययन/रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और अब तक उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का एनईपी का समग्र प्रभाव मूल्यांकन करने और उसके निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक संशोधन या नीति सुधार करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़+) 2024-25 के अनुसार, भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली में प्रमुख शैक्षिक संकेतकों में मापनीय सुधार पाया गया। इसमें लगभग 14.72 लाख स्कूलों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से बुनियादी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के लगभग 24.7 करोड़ छात्रों के आंकड़े हैं। शिक्षकों की संख्या 98.07 लाख से बढ़कर 1.01 करोड़ हो गई, जिसमें कुल 54.82 लाख महिला शिक्षक हैं, जो अधिक लैंगिक-संतुलित कार्यबल को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में छात्र शिक्षक अनुपात में सभी स्तरों पर सुधार हुआ। अनुपात अब बुनियादी स्तर पर 10, प्रारंभिक स्तर पर 13, मध्य स्तर पर 17 और माध्यमिक स्तर पर 21 प्रदर्शित होता है। ये अनुपात 1:30 के एनईपी मानदंड से अधिक मजबूत हैं, जो प्रत्येक छात्र पर सूक्ष्मता से ध्यान देने और बेहतर अधिगम परिणामों का समर्थन करते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 2023-24 की तुलना में प्रारंभिक परीक्षा (3.7% से 2.3%), मिडिल (5.2% से 3.5%), और माध्यमिक स्तर (10.9% से 8.2% तक) में स्कूल छोडने वाले बच्चों की दर में उल्लेखनीय कमी पाई गई है। वर्ष 2024-25 में सभी स्तरों पर छात्र प्रतिधारण दर में सुधार हुआ। बुनियादी स्तर 98.0 प्रतिशत से बढ़कर 98.9 प्रतिशत हो गया। प्रारंभिक स्तर 85.4 प्रतिशत से बढ़कर 92.4 प्रतिशत हो गया। मिडिल स्तर 78.0 प्रतिशत से बढ़कर 82.8 प्रतिशत हो गया। माध्यमिक स्तर 45.6 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गया। शैक्षणिक वर्ष 2024-

25 में मिडिल और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि दर्ज हुई। मिडिल स्तर 89.5 प्रतिशत से बढ़कर 90.3 प्रतिशत पर पहुंच गया। माध्यमिक स्तर 66.5 प्रतिशत से बढ़कर 68.5 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि उच्चतर शिक्षा में बढ़ी हुई पहुंच और उच्च ग्रेड में छात्रों की भागीदारी में वृद्धि को दर्शाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अधिगम परिणाम, पहुंच परिणाम, अवसंरचना, सुविधाएं, न्यायसंगत परिणाम आदि स्कूल शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से 73 संकेतकों को मिलाकर प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, राज्य (पीजीआई) विकसित किया है। वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की पीजीआई-राज्य रिपोर्ट https://pgi.udiseplus.gov.in/#/statepgi/home पर देखी जा सकती है। इसी तरह, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, जिला एक जिला-स्तरीय मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग विकेंद्रीकृत तरीके से स्कूल शिक्षा परिणामों की तुलना करने और उनमें सुधार हेतु किया जाता है। इसमें परिणाम, कक्षा प्रक्रियाएं, अवसंरचना, सुरक्षा, डिजिटल शिक्षण और शासन शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक की पीजीआई-जिला रिपोर्ट https://dpgi.udiseplus.gov.in/#aboutPgi पर देखी जा सकती है।

"परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024" का आयोजन दिनांक 04.12.2024 को पूरे भारत में किया गया था, ताकि बुनियादी, प्रारंभिक और माध्यमिक चरणों (क्रमशः ग्रेड 3, 6 और 9) के अंत में छात्रों में दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझा जा सके। सर्वेक्षण में राष्ट्रव्यापी 781 जिलों के 74,229 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्रों और 2.70 लाख शिक्षकों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं।

उच्चतर शिक्षा में, एक वार्षिक वेब आधारित 'अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई' उच्चतर शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण डेटा स्रोत है। एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) रिपोर्ट में एआईएसएचई 2014-15 की तुलना में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों और कॉलेजों की संख्या क्रमशः 760 से बढ़कर 1213 और 38498 से बढकर 46624 हो गई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है, जिसमें महिला नामांकन 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 46.07 लाख की तुलना में वर्ष 2022-23 में 69.13 लाख हो गया। अनुसूचित जनजाति छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 28.72 लाख हो गया है। कुल एसटीईएम नामांकन 99.76 लाख है। संकाय की संख्या वर्ष 2014-15 में 14.73 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 16.64 लाख हो गई है, जिसमें महिला संकाय की संख्या 5.7 लाख से बढ़कर 7.36 लाख हो गई है। कुल जीईआर वर्ष 2014-15 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 29.5 हो गया।

वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, क्यूएस रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं शामिल हैं, जबकि 2015 में यह संख्या 11 थी। 2025 के लिए क्यूएस विषय रैंकिंग में 79 भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं शामिल थे, जो पिछले वर्ष के 69 से 10 की वृद्धि है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 के अनुसार, 294 भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं की विशेषताएं हैं।

एनईपी का अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित होने की वजह से वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 में 48वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर पहुँच गई है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल करना शुरू कर दिया है।

****